

Sukhdev - 17 August

Q - "Punjab's fate after Ranjit Singh was fated as the impulse of neo-Victorian imperialism was bound to overwhelm it." Elucidate. [10 M]

उत्तर - रणजीत सिंह की निजी उपलब्धियों के होते हुए भी उनकी मृत्यु के बाद पंजाब में स्थायी राज्य ना बन सका तथा 1850 तक उसका विलय हो चुका के बाद ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में कर लिया गया।

यद्यपि पंजाब विलय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं तथा अनेक

इतिहासकारों ने इसे विलय ना मानकर विश्वासघात माना है क्योंकि -

1- अंग्रेजों की लार्ड (यशम सिंह गुह) के पश्चात् पंजाब का वास्तविक शासन

ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में था,

2- क्लाइव सिंग लेना ने किया था ना कि अकबरखान महारजा ने

3- कंपनी अकबरखान महारजा के संरक्षक के रूप में कार्यरत थी तथा अपने

रहित धार्मिक के प्रेश को सम्मिलित करने का कोई प्रयत्न नहीं था।

हालांकि, इसके बावजूद पंजाब का विलय वस्तुतः

19 वीं शताब्दी में बढ़ती ब्रिटिश साम्राज्यवादिता का ही प्रतीक है।

इसे निम्न तथ्यों से समझ सकते हैं -

1- ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव वस्तुतः बंगाल विजय के बाद ही पड़ गयी थी। इसके तहत कंपनी एक-एक करके भारतीय शाक्तियों को अलग-अलग जीता तथा विभिन्न रणनीतियों से इसके लिए भारतीय धन व सेना का ही प्रयोग किया। इसके तहत जहाँ पहले विदेशी शाक्तियों को परास्त किया (जैसे- फौजि), वहीं बाद में मैसूर, मराठा, तथा सिख आदि को परास्त किया। रणनीति के रूप में 'बहाक लान्छि' का प्रयोग भी इसका जीवन्त उदाहरण है।

2- लॉर्ड डोल्ब्रिगल के काल तक भारतीय परिस्थितियों प्रकृत; आक्रामक साम्राज्यवादी विस्तार के लिए अनुकूल हो गयीं। इसके कारण यह ले एक ओर तो ~~ए~~ डोली रिलायन्स के प्रति 'अधीनस्थता की नीति' अपनायी गयी तो दूसरी ओर अन्य माध्यमों जैसे युद्धों से साम्राज्यवादी विस्तार मित्रा गया।

3. इलहौली के काल तक 'इंडिय नीति' तथा किरा भी माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किये गये ,

4. पंजाब के विलय में पश्चिमोत्तर में प्राकृतिक सीमा स्थापित करने की आकांक्षा, अफगान सत्ताकाल के साथ ईरान-दक्षिण आक्रमण के भय ने भी भूमिका निभायी ,

यद्यपि विभिन्न ~~कारणों~~ गवर्नर जनरलों ने इसके लिए

विभिन्न रणनीति अपनायी किन्तु ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार की आकांक्षा

एकमात्र मूल तत्व था । क्योंकि एका एक परिणाम आगे चलकर 1857

की क्रांति व अन्ततः कंपनी शासन की समाप्ति के दृश्य में भी

आता है ।

Q- "The British Policy towards Indian states in 1818-1858 was one of isolation and non-interference tempered by annexation." Comment. [10 Marks]

उत्तर- 1813-1858 के काल तक भारतीय रिशासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 'अधीनस्थ पार्थक्य की नीति' कहा जाता है, इस काल में निम्न विशेषताएँ इसमें को मिलती हैं-

1- सभी बड़ी भारतीय देशी शक्तियों जैसे - मैसूर, मराठा आदि के पारलक्ष्य होने के पश्चात् ब्रिटिशों में साम्राज्य विस्तार की भावना व सर्वश्रेष्ठता के सिद्धान्त का विकास

2- आगे चलकर रिशासतों से की जाने वाली सन्धियों में पारस्परिकता व मैत्री संबंधों के लक्षण पर कंपनी के साथ अधीनस्थ सहयोग (subordinate cooperation) व कंपनी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकारने की बात

3- रिशासतों की समस्त बाह्य प्रभुसत्ता कंपनी के अधीन

4- यद्यपि सैद्धान्तिक तौर पर रिशासतें पूर्णतः स्वतंत्र तथापि आगे चलकर

ब्रिटिश प्रेजिडेंटों ने आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया। 1840 तक तो उत्तराधिकार के मामलों तथा मंत्रियों की नियुक्ति तक के मामलों में हस्तक्षेप किया जाने लगा।

5- 1833 के चार्टर एक्ट तथा विशेषतः 1840 के बांग्लादेशी लॉ पर गवर्नर जनरल को सामान्य विस्तार व रिवायतों के अधिकार को कदा भी नहीं दिया। इसके तहत बॉम्बे, कर्णाट, अजमेर तथा ओरिसा द्वारा कानून, जलौन का अधिकार दिया गया। 1840 के बाद के बाद तक तो अवध, नागपुर अली बड़ी रिवायतें 'खयमत के लिहाज' के आधार पर विलय कर ली गयीं।

हालांकि, कंपनी की यह नीति आलोचना के परे नहीं थी। अर्थात् -

- 1- रिवायतों को पूर्णतः अधीनस्थ बनाने की नीति अनसंख्य दानि, कुशासन तथा अकर्मण्यता के रूप में सामने आयी।
- 2- कंपनी की निर्विनास सर्वश्रेष्ठता स्थापित होने पर भी रिवायतों के

प्रति नीति पूर्णतः "अव्यवस्थित, अस्पष्ट और परस्पर विरोधी" रहे जिसके
तहत गवर्नर जनरल की व्यक्तिगत राय महत्वपूर्ण होती थी। इसी
का कारण है कि कभी कभी रियासत का विलय कर लिया जाता
था जो कभी रियासतों के आन्तरिक मामलों में महत्वपूर्ण की
बात की जाती थी (जैसे - कश्मीर 1846)

हालांकि रियासतों के प्रति यह नीति कंपनी के
लिए हानिकारक रही जो 1857 के विद्रोह के समय में दिखाता है
यही कारण है कि आगे चलकर आधिकारिक तौर पर 'विलय' व
अधिकार्य की नीति को लागू किया गया।